

भाजपा राहुल गांधी को घेरने की फिराक में है

पर, पार्टी में मतभेद हैं कि राहुल को पुनः संसद से

“डिस्क्वालिफाई” करा दिया जाता है तो वे “हीरो” के रूप में उभर सकते हैं तथा जनता में उनके प्रति सहानुभूति उभरेगी

‘सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य के आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता’

नई दिल्ली, 11 फरवरी। केन्द्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य आधार पर डिटेंशन से रिहा नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ को बताया कि अदालत के अनुरोध पर स्वास्थ्य आधार पर डिटेंशन को समीक्षा के लिए गंभीरता से विचार किया गया, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सका। मेहता ने कहा कि जेल मेनुअल के अनुसार, वांगचुक की 28 बार चिकित्सकीय जांच की गई है और वे स्वस्थ, ठीक-

■ केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया।

ठाक और सामान्य हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ पाचन संबंधी समस्या हुई थी, जिसका इलाज चल रहा है और कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। पिछली सुनवाई में जस्टिस वराले ने मौखिक रूप से वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता जताई थी और डिटेंशन पर पुनर्विचार का सुझाव दिया था, जिस पर न्यायमूर्ति कुमार ने भी सहमति व्यक्त की थी। पीठ ने यह भी टिप्पणी की थी कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें केंद्र सरकार वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को पूरी तरह नकार रही हो।

के अयोग्य ठहराने की दिशा में आगे बढ़ा जाए।

एक गुट का मानना है कि यह कदम अक्लमंदी नहीं होगा, क्योंकि इससे राहुल गांधी एक “हीरो” बन जाएंगे तथा और अधिक लोग उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे।

दूसरा गुट, जो सख्त रुख अपनाए हुए है, उसका कहना है कि राहुल गांधी को सबक सिखाना चाहिए। यदि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है, तो सरकार का आज्ञाकारी चुनाव आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव 6 महीने से पहले नहीं कराए जाएं।

लेकिन वे राहुल गांधी को अपमानित करने के लिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना चाहते हैं।

राहुल गांधी के मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ तीखे शब्दों ने सरकार को आहत किया है, लेकिन सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी के साथ क्या किया जाए, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘तीन साल से एक जगह तैनात अफसरों का तबादला होगा’

कोलकाता, 11 फरवरी। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही पद या जिले में तैनात प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया

■ चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले किया बड़ा फैसला।

है। बुधवार को आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

निर्देश के अनुसार, यह आदेश जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, उप-मंडलाधिकारी और अन्य जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होगा। इसके साथ ही, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) , उप-महानिरीक्षक (डीआईजी), पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी स्थानांतरित किया जाएगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी का रुख भारत के प्रति नरम हुआ

जमात के नेता कह रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध बांग्लादेश के लिए बेहद जरूरी हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 11 फरवरी। बांग्लादेश में गुस्से को होने वाले अहम चुनाव से एक दिन पहले, जिसमें नई सरकार चुनी जाएगी और लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा, जमात का एक प्रमुख उम्मीदवार चर्चा में है। ढाका-14 सीट से जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार बैरिस्टर मीर अहमद बिन कासेम अरमान एक हाई-प्रोफाइल चुनाव लड़ रहे हैं।

अगस्त 2024 से बांग्लादेश में मुहम्मद युनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है, क्योंकि जुलाई 2024 में हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली सरकार को हटा दिया गया था।

तब से ध्यान इस बात पर है कि चुनाव के बाद बांग्लादेश पर कौन शासन करेगा। इस दौड़ में दो मुख्य दावेदार हैं,

■ जमात के एक कद्दावर नेता, मीर अहमद बिन कासेम अरमान, जो ढाका-14 से चुनाव लड़ रहे हैं, का मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ताकतवर नेता संजीदा इस्लाम से है। अरमान ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। हमें साथ मिलकर काम करना होगा।

■ बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं और उसके बाद वहाँ निर्वाचित सरकार सत्ता में आएगी। फिलहाल मरहूम खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आगे चल रही है, जिसे उदारवादी छवि के कारण सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है।

■ लेकिन, जमात का बदलता रुख संकेत दे रहा है कि अपने भारत विरोधी और पाक समर्थक ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी जमात भारत के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाश रही है।

पहली है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), और दूसरी है, बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी, जो एक कट्टर इस्लामी पार्टी है और समाज के सभी

वर्गों के मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है।

ढाका-14 सीट से जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार अरमान एक हाईप्रोफाइल चुनाव लड़ रहे हैं। वे बांग्लादेश में जबरन गायब किए जाने की घटनाओं के पीड़ित रह चुके हैं। वे बीएनपी की उम्मीदवार संजीदा इस्लाम उर्फ तुली के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो 'मदर्स कॉल' नाम के संगठन की समन्वयक हैं। यह संगठन जबरन गायब किए गए लोगों के परिवारों द्वारा बनाया गया है। अरमान ने कहा, “हम फिर से तानाशाही नहीं चाहते। मैं जबरन गायब किए जाने का शिकार रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जनमत संग्रह में 'हाँ' की जीत होगी।”

अरमान जमात के बड़े नेताओं में से एक हैं और भारत के साथ मिलकर काम करने की वकालत कर रहे हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पैनग्विन रैंडम हाउस को नोटिस

नई दिल्ली, 11 फरवरी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल (विशेष प्रकोष्ठ) ने पैनग्विन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी कर पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना

■ दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराने के मामले में इस पब्लिशिंग हाउस से जवाब तलाब किया है।

प्रमुख की पुस्तक को लेकर दर्ज मामले में और सीक्रेट एक्ट व कॉपी राइट की धाराएं भी जोड़ी हैं।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह नोटिस ऐसे समय में जारी किया गया, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-रेणु मिश्रल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 फरवरी। भाजपा ने राहुल गांधी को घेरने के लिए कमर कस ली है, और उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रियों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उसे लेकर भाजपा कार्रवाई करना चाहती है।

यह अवसर आज तब आया, जब बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मंत्री हरदीप पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम एप्टीन फाइल्स में शामिल होने के संबंध में लिया।

इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी पर दबाव था, क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका की अदालतों में एक मामला चल रहा था, और चूंकि अडानी मोदी के वित्तीय सहयोगी और आर्किटेक्ट हैं, इसलिए प्रधानमंत्री पर दबाव था और उन्होंने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के मामले में

■ पर, दूसरी सोच यह है कि राहुल गांधी को सबक सिखाना जरूरी है तथा अगर भाजपा से नज़दीकी रखने वाले चुनाव आयुक्त हों तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव छः महीने नहीं होने दे।

■ पर, बहरहाल अभी तो इस बात पर भाजपा में आम सहमति बनी है कि राहुल गांधी के खिलाफ सदन में “प्रिविलेज” प्रस्ताव तो लाया ही जाए, जिस तरह बजट पर बोलते हुए उन्होंने मंत्री हरदीप पुरी व बिज़नैसमैन अनिल अंबानी पर लांछन लगाया कि उनके नाम “एप्टीन फाइल्स” में आये हैं।

■ भाजपा, इस बात से भी काफी उत्तेजित है कि जिस तरह राहुल गांधी ने प्र.मंत्री पर कई आरोप लगाए, अमेरिका के सामने आत्म समर्पण किया। पर, दुविधा यह है कि भाजपा निश्चित नहीं कर पा रही है कि राहुल गांधी से किस तरह डील किया जाए।

ट्रम्प के सामने समर्पण कर दिया।

सूत्रों का कहना है कि एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 हस्ताक्षरों की आवश्यकता

होती है।

सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार और भाजपा में इस पर मतभेद है कि क्या राहुल गांधी को सदन की सदस्यता

‘डॉक्टर्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से बाहर रखा जाए’

एक जनहित याचिका में की गई इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जवाब मांगा

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को, एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया तथा जवाब मांगा यह याचिका हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (इंडिया) एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है, जिसमें 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत चिकित्सा पेशेवरों को बाहर करने की मांग की गई है।

इस जनहित याचिका में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून, जो मरीजों को उपभोक्ता अदालतों में दावा करने की शक्ति देता है, चिकित्सा तापरवाही के लिए हर्जाना मांगने का अधिकार प्रदान करता है, और इसमें चिकित्सा पेशेवरों को शामिल करना

■ सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स द्वारा दायर जनहित याचिका पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

■ उपभोक्ता/संरक्षण कानून में चिकित्सा सेवा को भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के एक फैसले में कहा था कि अगर डॉक्टर निःशुल्क सेवा नहीं दे रहे हों तो उनके द्वारा दिया गया इलाज उपभोक्ता सेवा के दायरे में ही आता है।

“डॉक्टर-पेशेंट रिश्ते के विश्वास को कमजोर करता है और चिकित्सा प्रैक्टिस की नैतिक नींव को नष्ट करता है।”

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एनबी अंजारिया की पीठ ने हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (इंडिया) एसोसिएशन (एएचपी) और इसके पूर्व अध्यक्ष, बेंगलुरु के एक डॉक्टर द्वारा

दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि चिकित्सा सेवाओं पर उपभोक्ता कानून लागू करने से चिकित्सा प्रैक्टिस में रक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। इसमें कहा गया है कि चिकित्सा लापरवाही की जांच करने के लिए अन्य, अधिक उपयुक्त तंत्र हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रितु तावड़े बर्नी मुम्बई की मेयर

मुंबई, 11 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पार्षद रितु तावड़े बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की निर्विरोध महापौर चुनी गई हैं। वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) के पार्षद संजय घाडी उपमहापौर बने हैं। इसकी घोषणा बुधवार को बीएमसी मुख्यालय में निगम आयुक्त भूषण गगरानी ने की। आयुक्त गगरानी ने कहा कि महापौर पद के लिए केवल भाजपा पार्षद

■ शिवसेना (शिंदे गुट) के संजय घाडी बने डिप्टी मेयर।

रितु तावड़े का ही नामांकन प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें बीएमसी का महापौर घोषित किया जाता है। इसी तरह, उपमहापौर पद के लिए केवल संजय घाडी का ही नामांकन प्राप्त हुआ, इसलिए उन्हें उपमहापौर घोषित किया जाता है।

इस दौरान, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने रितु तावड़े और संजय घाडी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 फरवरी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अमेरिका के साथ हुए व्यापार और टैरिफ समझौते को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने देश के कृषि और डेयरी मार्केट को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोलकर “भारत माता को बेच दिया” है।

गांधी ने गजरते हुए कहा कि सरकार को “शर्म आनी चाहिए”। उन्होंने विपक्षी नेताओं की इस आलोचना को दोहराया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते ने अमेरिकी सामान को भारत में आने की अनुमति देकर करोड़ों किसानों, खासकर छोटे

और सीमांत किसानों, तथा उनसे जुड़े उद्योगों की रोजी-रोटी को खतरे में डाल दिया है।

उनकी आलोचना का मुख्य आधार यह दावा था कि अमेरिका के टैरिफ, 2025 से पहले के औसत तीन प्रतिशत, जो बेसलाइन एमएफएन (मोस्ट फेवर्ड नेशन) दरों का हिस्सा थे, से बढ़कर इस महीने हुए समझौते के बाद 18 प्रतिशत हो गए हैं।

बीच में, डॉनल्ड ट्रंप ने अनुचित टैरिफ की शिकायत की और “रैसिप्रोकल” शुल्क लागू करने की घोषणा की, तब ये दरें 50 प्रतिशत तक पहुंच गई थीं। इसके बाद भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत की “पैनल्टी” भी लगाई गई थी।

■ राहुल गांधी ने कहा, ट्रेड डील से अमेरिका का टैरिफ तीन प्रतिशत से बढ़ाकर अब 18 प्रतिशत करना स्वीकार कर लिया गया है।

■ ट्रेड डील में राहुल गांधी के अनुसार, हम पर लागू टैरिफ तीन प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है. पर, अमेरिका पर भारत द्वारा लगाया गया टैरिफ अब 16 प्रतिशत से घट कर जीरो प्रतिशत हो गया है।

■ साथ ही, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारे ऊपर कई प्रतिबद्धताएं लागू हो गई हैं, नई ट्रेड डील से, पर, अमेरिका पर कोई शर्त या प्रतिबद्धता लागू नहीं हुई है।

■ राहुल के अनुसार, भारत नई ट्रेड डील में 500 अरब डॉलर की एनर्जी व अन्य टैक्नॉलजी प्रोडक्ट्स अमेरिका से खरीदेगा, पर, भारत का अमेरिका को निर्यात जो अभी 46 अरब डॉलर है, से बढ़कर 176 अरब डॉलर ही हो पाएगा।

गांधी ने कहा, “आपने भारत को बेच दिया... क्या भारत को बेचने में

आपको शर्म नहीं आती?” उन्होंने कहा, “इतिहास में पहली बार हमारे किसान

बड़े संकट का सामना कर रहे हैं और आपने हमारे गरीब किसानों को कुचलने

के लिए दरवाजा खोल दिया है।”

उन्होंने कहा, “किसी भी प्रधानमंत्री ने पहले ऐसा नहीं किया।” उन्होंने जोर देकर आगे कहा कि इस समझौते में “कोई तर्क नहीं” है।

उन्होंने कहा, “आपने यह क्या किया... शुरुआत में तीन प्रतिशत औसत था। अब यह 18 प्रतिशत हो गया है, यानी छह गुना बढ़ोतरी। अमेरिका से आयात 46 अरब डॉलर से बढ़कर 146 अरब डॉलर हो जाएगा... यह पूरी तरह बेतुका है।”

गांधी ने कहा, “उनकी हमारे प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है... लेकिन हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता है।” गांधी उस प्रावधान का जिक्र कर रहे थे, जिसमें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

**राजस्थान बजट में क्या सस्ता-क्या महंगा
स्टांप ड्यूटी पर सरचार्ज 3 फीसदी
बढ़ा; डी.एल.सी. दरें भी बदली**

- हालांकि दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी
- सरकार ने लोन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन शुल्क आधा किया
- फार्म हाउस की जमीन की रजिस्ट्री करवाना महंगा हुआ

- 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमिटी गठन, किसानों को 25 हजार करोड़ रु. का ब्याज मुक्त ऋण तथा लावारिस-विमर्दितों के मुफ्त इलाज की घोषणा
- मेधावी विद्यार्थियों को 20 हजार रु. का ई-वाऊचर तथा स्कूली बच्चों के लिए जादुई पिटारे की घोषणा
- महिला वर्ग को साधने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए की

जयपुर (रिस) राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में स्टायम पेपर पर लगने वाले सारचाज को 3 फीसदी तक बढ़ा दिया है। इस फीस का असर सोचें तो पर स्टायम पेपर खरीदने पर देखने को मिलेगा। यही नहीं सरकार ने कुछ अलग-अलग कैटेगोरी को भी यमीनों को डीएलसी दरों को बढ़ावा करते हुए पूरे प्रदेश में एक समान दर लागू करने का आदेश जारी किया है। इन दोनों ही निर्णयों से जचल ससम्पाधियों को रजस्ट्री भी महगी होगी।

जजने में सरकार ने ब्रैक या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले लोन या ऋण के लिए तैयार होने वाले डॉक्यूमेंट के रजस्ट्रेशन पर लगने वाले चार्ज को भी आधा कर दिया है। अभी तक ऐसे डॉक्यूमेंट के रजस्ट्रेशन की फीस

- 1 फीसदी लगती थी, लेकिन इसमें कम करके आधी यानी 0.5 फीसदी कर दिया है। साथ ही इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित कर दी है। यानी अगर 0.5 फीसदी चार्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा बनती है तो सरकार केवल 1 लाख रुपए ही लेगी। इसी तरह इन डॉक्यूमेंट पर लगने वाली स्टायम ड्यूटी को भी 0.25 फीसदी से आधा यानी (0.125 फीसदी) कर दिया है। वहीं इसकी अधिकतम सीमा को भी 15 लाख रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया है।

सरकार ने अब फार्म हाउस की जमीन की आरक्षित दरों (डी.एल.सी. रेट) में भी बढ़ोतरी की है। सरकार पहले ही फार्म हाउस की जमीन का बाजार मूल्य वहां की एग्रीकल्चर जमीन के दर 1.5 गुना मानते हुए रजस्ट्री

हरीद्वार। पतंजलि अपने प्रत्येक उत्पाद में गुणवत्ता, शुद्धता और उपभोक्ता सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसका प्रतिबन्धन जो एक और सशक्त वैज्ञानिक मान्यता उस समय मिली, जब पतंजलि शहद पर किया गया विस्तृत शोध विश्वप्रसिद्ध “एससवियर” प्रकाशन के प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल “एपलाइड फूड रिसर्च” में प्रकाशित हुआ। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि जो कहता है, वही

कार्यालय, नगरपालिका मण्डल, बीदासर (चूक) राज०
E-Mail : nagarpalikabidasar@gmail.com **Phone No. : 01560 – 260208**
क्रमांक-नपासी / 2025- 26 / 3542 **दिनांक- 05.02.2026**

ई-निविदा सूचना सख्या 11/2025- 26

नगरपालिका बीदासर में निम्नलिखित सफाई/सेवा/निर्माण कार्यो के लिये निम्नांक के अनुरात नगर निगम बीदानेर/ नगरपालिका बीदासर में पजीकुत व अन्य विभागो के 'A' एवं 'AA' श्रेणी में पजीकुत सदिको से निमित्त पत्र में ई-प्रक्रासुत प्रक्रिया से निविदा से कार्या ईद ओंगलातुन दिनांक ओमोत्रि की जारी है। निविदा कार्य दिनांक 05.02.2026 को 17:00 बजे से तथा निदिनांक 17.02.2026 सपर 18.00 बजे तक ओंगलातुन निविदा जमा करवाय जा सकती है। निविदा शर्त ओद संपूर्ण विवरण वेबसाईत <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।
<http://www.sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।

NIB CODE DLB2526B1332

UBN NO - DLB2526WSRC33386	UBN NO - DLB2526WSRC33388
UBN NO - DLB2526WSRC33389	UBN NO - DLB2526WSRC33390
UBN NO - DLB2526WSRC33390	UBN NO - DLB2526WSRC33391
UBN NO - DLB2526WSRC33394	UBN NO - DLB2526WSRC33395
UBN NO - DLB2526WSRC33396	UBN NO - DLB2526WSRC33397
UBN NO - DLB2526WSRC33398	UBN NO - DLB2526WSRC33399
UBN NO - DLB2526WSRC33400	UBN NO - DLB2526WSRC33401

अध्यक्ष

राज.सं/चय/सी/25/19567	नगरपालिका, बीदासर	अधिसभाी अधिकारी
		नगरपालिका, बीदासर

जयपुर (कास)। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताया। पायलट ने कहा कि पहले केन्द्रीय बजट में भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान की अनदेखी की गई और अब राज्य सरकार ने अपने बजट

- सचिन पायलट ने कहा कि “पहले केन्द्रीय बजट में राजस्थान की अनदेखी हुई, अब राज्य सरकार ने भी लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है।”
- पायलट ने कहा कि “हाईकोर्ट में सरकार ने हफलनामे के माध्यम से स्वीकार किया था कि प्रदेश की स्कूलों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन बजट में मात्र 500 करोड़ रु. का प्रावधान दिखाता है कि सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा की चिंता नहीं है।”

माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग की आशाओं पर धीरे-धीरे फिदा है। याल्पल ने कहा कि मलालाबाड़ की स्कूल में हुए हादसे पर गान्धन लेले हुए रास्थान हाईकोर्ट ने सरकार को फटी कड़कर लगाई थी और सरकार हलतलमल मे माध्यम से यह स्वीकार भी किया था कि प्रदेश की स्कूल की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रूपयों की आवश्यकता है। बावु इसके राज्य बजट में मात्र 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना यह बतल है कि राज्य सरकार को विद्यार्थियों सुरक्षा की कोई चिन्ता नल है।

क प्रदेश की स्कूलों
21 हजार करोड़
कता है। बावजूद
मात्र 500 करोड़
या जाना यह बताता
को विद्यार्थियों की
नहीं है।

स्वीकार भी किया था कि प्रदेश की स्कूलों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रूपयों की आवश्यकता है। बावजूद इसके राज्य बजट में मात्र 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना यह बताता है कि राज्य सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है।

-विधानसभा संवाददाता-

नयपुरवा राजस्थान के बजट में वित्त मंत्री दिव्या कुमारी ने कहा कि आरालवी पर्वतमाला का एक बड़ा हिस्सा जयपुर, अलवर, भरतपुर, सर्वाई माधोपुर तथा झुंझुनार में आता है। साल 130 करोड़ रुपये की लागत से आरालवी पर्वतमाला की करीब 4 हजार हेक्टेयर भूमि को गन्गाह पर पक्की दीवार बनाई जाएगी। प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों को सैनिकली कक्षा जाएगा। दिया कुमारी बजट में घोषणा की है कि, प्रदेश के उत्तरी, पूर्वी सीमाओं, उनके आश्रितों और श्रीगंगा-गंडक नदी सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध हो सकें, ऐसे लिए जोधपुर, शेरादू, टोंक, फलोदी, खैखेल, ब्यानर, झुंझुनार और श्रीगंगानगर में वॉर म्यूजियम, इंडस्ट्री ऐंड सीमेंट कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। पहले चरण में जोधपुर, शेरादू, झुंझुनार और टोंक में 36 करोड़ की लागत से इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा।

सीकर और झुंझुनार में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे की घोषणा की गई है। 8 जिलों में 3000 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने शेखावाटी के लिए यमुना जल परियोजना का काम जल्द शुरू होने की घोषणा की है। इस परियोजना पर 32000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकासर जूली ने प्रश्नवाला सवाल की तीसरे बजट को पूरी तरह नीरस और निराशाजनक करार देते हुए कहा कि सरकार घोषणाओं तक सीमित है, जमीनी क्रयान्वयन बेहद कमजोर है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने 2718 बजट घोषणाएं की, लेकिन से केवल 20 प्रतिशत ही पूरी हो गई हैं। 30 प्रतिशत घोषणाएं अब सरकार शुरू नहीं हुई, जबकि 40 प्रतिशत पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 के सपने दिखा रही है, लेकिन वर्तमान समस्याओं की कुछ जेबे को तैयार नहीं है। रिफाइनरी शुल्क करने की पूर्व घोषणा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तय समयसीमा भीत तक के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा। बजट में मेंटल हेल्थ चेकअप सेंटर की घोषणा पर जूली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को पहले अपना मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण घोषणा चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नीतियां से कर्मचारी और आमजन परेशान हैं। प्रस्टेम में रोज हजारों को रहे हैं, जो सिस्टम की लापरवाही और खराब सड़कों का परिणाम हैं। आंगनबाड़ कार्यकर्ताओं के लिए की गई घोषणाओं को भी उन्होंने 'जादू के पिंटेरे' जैसा बताया। जूली ने 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि ये आंकड़े किस आधार पर तय किए गए हैं। सरकार ने दो वर्षों में ही प्रदेश को भारी कर्ज में डुबो दिया है। 1000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, निष्पक्ष परियोजनाओं और निवेश के दावों पर भी उन्होंने स्पष्ट जवाब मांगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बजट को इतिहास का सबसे नीरस बजट बताया। उन्होंने कहा कि स्कूल मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ की आवश्यकता के मुकाबले मात्र 550 करोड़ रुपये खर्च गए हैं।

लागया कि सरकारी नीतियों से कर्मचारी और आमजन परेशान हैं। प्रदेश में रोज हाजिर हो रहे हैं, जो सिस्टम की लापरवाही और खराब सड़कों का परिणाम हैं। आंगनबाड़ कार्यकर्ताओं के लिए की गई घोषणाओं को भी उन्होंने 'जादू के पिण्डों' जैसा बताया। जूली ने 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि ये आंकड़े किस आधार पर तय किए गए हैं। सरकार ने दो वर्षों में ही प्रदेश को भारी कर्ज में डुबो दिया है। 1000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, निष्पन्न परियोजनाओं और निवेश के दावों पर भी उन्होंने स्पष्ट जवाब मांगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बजट को इतिहास का सबसे नीरस बजट बताया। उन्होंने कहा कि स्कूल मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ की आवश्यकता है मुकाबले मात्र 550 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

प्रत्यक्ष संख्या 7
(देखिये नियम 21)

**कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर**

**राजस्थान सार्वजनिक प्रशास्य
अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के
अधीन नोटिस**

सम्बन्धित सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 34/2026
(नाम निर्णय तथा निवास स्थान)

चूंकि प्राणी श्री राजेश कुमार शर्मा श्री मंगर लाल मोदी
राजस्थानी दायिमागी माली राजेश द्विवेदी वरुदा वरुदा
रोड सीकर मे राजस्थान सार्वजनिक प्रशास्य
अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत
अनुमति मेकेवल दिशाक्षर संस्थान दायिमागी माली
वजान रोड सीकर की सम्बन्ध मे जांच किये जाने के
लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रस्तुत शर्तियों
के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रशास्य जिसकी को की जा
रही है मे हित रखने वाले सम्बन्ध व्यक्तियों के नाम,
व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित
की जा रही है कि वे इस नोटिस के जारी होने की
तारीख से सात दिन के भीतर आवे प्रस्तावे मे
सम्बन्ध मे सम्बन्धित, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
यदि यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त
निर्दिष्ट अधिनियम के भीतर कोई अपराध नहीं की
गई तो आवे आवेदन पत्र या निर्धारित माली से निर्णित
किया जावेता तथा जांच प्रविष्टि राशित मे निष्कर्ष
अभिज्ञित किया गया।

आदि दिनांक 30. 01. 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा
कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

दायित्व तारीख पेशी 07. 04. 2026

**सह
अवर**

**सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर**

जयपुर। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री (फोर्ट) के कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. अरुण अग्रवाल ने बजट 2023-24 पर व्यापार सारक के बजट को व्यापारियों व उद्योगों को नई दिशा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री एन एम कुलचरानी ने बजट में व्यापारियों के लिए एकल विद्युती प्रणाली, व्यापार प्रोत्साहन नीति, और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसे महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इनसे व्यापार करना आसान होगा और व्यापारियों को प्रचार प्रसार प्रदान होगा। बजट में उद्योगों के लिए फ्लैट-टैक्स व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र, और विशेष औद्योगिक पार्क जैसे घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पर्यटन स्थलों के विकास प्रचार, स्थानीय कला-संस्कृति को बढ़ावा देने, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन किसाँ के लिए नई तकनीकी व संसाधनों के प्राधान्य सहानी है।

Fax &Phone: 01559-222039

संक्र. - न.पा.रा./ताभीर / 2025-26/7601

दिनांक :- 11/02/26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निर्माकित आवेदकों द्वारा पट्टा नामान्तरण / भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। जिस किसी व्यक्ति को इस संबंध में आपति हो वह विज्ञिप्त प्रकाशन के सात दिवस में नगर पालिका कार्यालय में लिखित में पेश कर दें। सम्पूर्ण जानकारी के लिए नगरपालिका राजगढ (चूरू) की पट्टा नामान्तरण / भवन निर्माण शाखा कमरा नं. 02 से पता करें। समयावधि निकलने के पश्चात आपति विचारानीय नहीं होगी। विवरण निम्नानुसार है:-

पट्टा नामांतरण				
1	824/17.07.2025	श्रीमती अमीना पत्नी गोसिन खान, वार्ड नं. 22, मौहल्ला नरडियान, राजगढ़, चूरू	आवासीय	16.81 वर्गमीटर
2	729/04.12.2024	श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री मदनलाल शर्मा, वार्ड नं. 07 मौहल्ला भगवानी देवी हास्पिटल के पास कोठारी बिल्डिंग, राजगढ़, चूरू	आवासीय	21.92 वर्गमीटर
3.	867-1/16.12.2025	श्री हबिब सुलेमान पुत्र श्री सुलेमान, वार्ड नं. 19, मौहल्ला सोनी हास्पिटल के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	32.22 वर्गमीटर
4	858-1/12.11.2024	श्री नरेन्द्र गोयल पुत्र श्री सुरेश गोयल, वार्ड नं. 11 मौहल्ला शिव बगीची के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	141.92 वर्गमीटर
5	911/22.01.2026	श्री सन्दीप सोनी पुत्र श्री अन्तराम सोनी, श्रीमती नेहा पत्नी श्री नेहा पत्नी श्री प्रितम सिंह, वार्ड नं. 09 मौहल्ला मौहता चौक. राजगढ़, चूरू	आवासीय	67.82 वर्गमीटर
6.	705/21.10.2024	श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री नन्द किशोर, वार्ड नं. 15 मौहल्ला मुरली मनोहर मन्दिर के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	66.23 वर्गमीटर
7	693/07.10.2025	श्रीमती जैतुन पत्नी श्री सराजुदीन, वार्ड नं. 31 मौहल्ला लुदीबास, शीतला बाजार, राजगढ़, चूरू	आवासीय	18.59 वर्गमीटर
8.	914/09.02.2026	श्रीमती फूलवती पुनियां पत्नी श्री रणवीर सिंह, वार्ड नं. 10 मौहल्ला बागवास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	27.58 वर्गमीटर
9.	915/09.02.2026	श्री राजकुमार पुत्र श्री दरियां सिंह, वार्ड नं. 18 मौहल्ला पिलानी मोड़ के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	37.15 वर्गमीटर
10.	905/30.12.2025	श्री पवन मुदगल पुत्र श्री प्रेम प्रकाश, वार्ड नं. 14 नया 09 मौहल्ला गणगौर चौक के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	81.75 वर्गमीटर
भवन निर्माण स्वीकृति				
1.	709/29.12.2025	श्री रामावतार सोनी पुत्र श्री बनवारी लाल सोनी, वार्ड नं. 17 नया 21. मौहल्ला सोनी हारपीटल के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	70.60 वर्गमीटर
2.	636/11.02.2025	श्रीमती प्रीतमा पत्नी श्री संतोष कुमार व नेहा जैन पत्नी श्री अजय कुमार कोचर, वार्ड 14 हाल वार्ड 10, मोहल्ला रेल्वे स्टेशन के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	89.18 वर्गमीटर
3.	705/16.12.2025	श्री हबिब सुलेमान पुत्र श्री सुलेमान, वार्ड नं. 19, मौहल्ला सोनी हास्पिटल के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	32.22 वर्गमीटर
4.	715/09.02.2026	श्रीमती फूलवती पुनियां पत्नी श्री रणवीर सिंह, वार्ड नं. 10 मौहल्ला बागवास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	27.58 वर्गमीटर
5.	716/09.02.2026	श्री राजेन्द्र व राकेश पुत्रगण श्री धर्मपाल, वार्ड 11. मोहल्ला विद्युत विभाग के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	23.22 वर्गमीटर
6.	717/09.02.2026	श्री चन्दन सिंह पुत्र इन्द्राज सहारण, वार्ड 10, मोहल्ला रेल्वे स्टेशन के पास, राजगढ़, चूरू	व्यवसायिक (3rd Floor)	68.95 वर्गमीटर
(कृष्ण कुमार छाबा) अधिकाारी नगर पालिका राजगढ़ (चूरू)				

वर्ष 23-24 के मुकाबले इस वर्ष बजट का आकार 40 प्रतिशत बढ़ा- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 24-25 की 93 प्रतिशत तथा 25-26 की 86 प्रतिशत बजट घोषणाओं की क्रियान्विति हो गई

जयपुर, 11 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट 2026-27 तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं पर खरा उतरने, और सबका साथ, सबका

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वर्ष के बजट में वित्त वर्ष 23-24 की तुलना में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए दोगुनी, चिकित्सा-स्वास्थ्य के लिए 53 प्रतिशत अधिक तथा ग्रीन बजट पर 20.81 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान किया गया है।

विकास के तीन कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए बनाया गया है।
बुधवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी द्वारा राज्य बजट 2026-27 प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बजट में आधारभूत संरचना



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में राज्य बजट 2026-27 प्रस्तुत किए जाने के बाद पत्रकारों से वार्ता की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ. प्रेमचन्द बैरवा मौजूद थे।

के सुदृढ़ीकरण सहित, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिससे राजस्थान विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में 1441 बजट घोषणाएं की थी, जिनमें से 1246

घोषणाओं (86 प्रतिशत) और वर्ष 2024-25 के बजट की 1277 घोषणाओं में से 1188 घोषणाओं (93 प्रतिशत) की क्रियान्विति की गई है।
उन्होंने कहा कि इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय 53 हजार 978 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो 2023-24 से 2 गुना से अधिक है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जो 2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक है। ग्रीन बजट में 33 हजार 476

करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष से 20.81 प्रतिशत अधिक है। शर्मा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए बजट में राजस्थान स्टेट टैस्टिंग एजेंसी की घोषणा की गई है।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया सहित, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

‘डॉक्टरों को उपभोक्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं में अनुचित व्यापार प्रथाओं या खामियों के लिए समाधान प्राप्त करने का एक तंत्र प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 1995 के अपने फैसले में यह माना था कि चिकित्सा सेवाएं भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के धारा 2(1)(0) के तहत “सेवा”

के दायरे में आती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 1995 को दिए गए अपने फैसले में यह कहा था: चिकित्सक द्वारा एक मरीज को दी गई सेवा (जब तक कि डॉक्टर किसी मरीज को मुफ्त सेवा न दे रहे हों या व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत सेवा प्रदान न कर रहे हों), परामर्श, निदान और उपचार (चिकित्सीय और शल्य चिकित्सा दोनों) के रूप में दी गई

सेवा, अधिनियम के धारा 2(1)(0) के तहत “सेवा” के दायरे में आएगी।
“यह तथ्य कि चिकित्सा पेशेवर भारतीय चिकित्सा परिषद और/या भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत स्थापित राज्य चिकित्सा परिषदों के अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन होते हैं, उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को (उपभोक्ता संरक्षण) अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं कर सकता।”

पैनग्विन रैंडम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जब पुस्तक की स्थिति और अनधिकृत संस्करणों के कथित अवैध प्रसार के विरोध में दावे किए जा रहे हैं, जिससे प्रकाशक, पूर्व सेना प्रमुख और वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियां एक व्यापक सार्वजनिक विवाद में शामिल हो गई हैं। पुलिस के अनुसार विशेष प्रकोष्ठ ने नोटिस के माध्यम से प्रकाशक से औपचारिक रूप से संपर्क कर कई सवाल पूछे हैं और उनके विस्तृत जवाब मांगे हैं।

‘राष्ट्रगीत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
इस साल की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान, राष्ट्रीय गीत पर आधारित कई झांकियां प्रदर्शित की गई थीं। नए नियमों के तहत, राष्ट्रीय गीत के छह अन्तर्ों का संस्करण, जो 3 मिनट 10 सेकंड तक चलता है, विशेष सरकारी आयोजनों में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके मुकाबले, “राष्ट्रगान” जन गण मन 52 सेकंड का होता है। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि मृदंगम की ध्वनि राष्ट्रीय गान से पहले बजाई जाएगी। जब वन्दे मातरम् और जन गण मन दोनों बजाए जाएंगे, तो राष्ट्रीय गीत पहले बजाया जाएगा। पिछले नवंबर में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कड़ी आलोचना की थी कि उन्होंने “मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए गीत के महत्वपूर्ण अन्तरे हटा दिये थे।” मोदी ने कहा था कि “गीत को टुकड़ों में बांट दिया गया, और इससे देश के विभाजन के बीज बोए गए।” संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय गीत पर चर्चा के दौरान, सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस और कहा-सुनी हुई थी।

‘तीन साल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जिन अधिकारियों ने किसी विशेष जिले या पद पर तीन वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है, उन्हें स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा।

‘आपने भारत माता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कहा गया है कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर के ऊर्जा और तकनीकी उत्पाद खरीदेगा। उन्होंने कहा, “हम मूर्खों की तरह खड़े हैं। हमारा टैरिफ 18 प्रतिशत तक बढ़ गया है... और उनका 16 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गया है।”
इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने हस्तक्षेप किया और गांधी से, जो विपक्ष के नेता भी हैं, अमेरिका के साथ हुए सवझौते पर अपने दावों के समर्थन में तथ्य पेश करने को कहा।

रिजिजू ने कहा, “भारत की प्रगति से आपको खुशी नहीं होती। कांग्रेस ने 2014 तक देश को कमजोर किया और अब असंतुष्ट है..”
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को “अब तक का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री” भी बताया।

वृंदावन के होटल में उद्घाटन के दिन ही आग लगी

मथुरा, 11 फरवरी। वृंदावन के रुक्मिणी विहार स्थित नव निर्मित सिद्धि विनायक होटल में बुधवार को उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद भीषण आग लग गई। आग लगते ही होटल के अंदर घना धुआं भर गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में तीन लोग झुलस गए, जबकि करीब 40 लोग होटल के अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर बाद अचानक होटल की ऊपरी मंजिल से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे परिसर में धुएं का गुबार फैल गया। होटल में मौजूद मेहमान और कर्मचारी घबरा गए ?

कई लोग कमरों और गलियारों में फंस गए थे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बना दिया।

हादसे में होटल मालिक सुभाष अग्रवाल के समथी हरिमोहन के बेटे विनीत की तबियत अधिक बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, आग की चपेट में आकर तीन लोग झुलस गए। घायलों में

- आग के दौरान 40 लोग अंदर फंस गए थे, तीन लोग झुलस गए हैं
- जिलाधिकारी ने बताया कि होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी तथा होटल मालिक के परिवार के तीन लोग झुलस गए।

दो बच्चे कार्तिक और समर तथा एक महिला जिया शामिल हैं। सभी को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्रशासन के अनुसार, सभी घायल खतरे से बाहर हैं।

जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि रुक्मिणी विहार स्थित सिद्धि विनायक होटल में उद्घाटन के दिन शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। उन्होंने कहा, इस घटना में होटल मालिक के परिवार के तीन सदस्य झुलस गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। स्थिति अब नियंत्रण में है।

बताया जा रहा है कि होटल में कुल 24 कमरे हैं और बुधवार को ही इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था।

एस्टीन से मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के तहत हुई- हरदीप पुरी

नई दिल्ली, 11 फरवरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार (11 फरवरी) को बजट सत्र के दौरान एस्टीन फाइल्स का जिक्र किया, जिसके बाद देश में राजनीति गरमा गई है। इसे लेकर केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि युवा नेता (राहुल गांधी) को पता होना चाहिए कि एस्टीन फाइल्स गलत कामों और आपराधिक मामलों से संबंधित हैं। केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जेफरी एपस्टीन से मुलाकात की थी, लेकिन यह मुलाकात

■ राहुल गांधी द्वारा जिक्र किये जाने के बाद मंत्री पुरी ने स्पष्ट किया।

अंतरराष्ट्रीय पीस इन्स्टीट्यूट (आईपीआई) के एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहते हुए हुई थी। उन्होंने कहा, साल 2009 में जब मैं अमेरिका में राजदूत था, तब ये मुलाकात हुई। सारी सच्चाई पब्लिक डोमेन में मौजूद है। सार्वजनिक रूप से करीब 3 मिलियन ईमेल हैं। इसके 8 साल बाद मैं मंत्री बना। इस दौरान 3-4 मुलाकातों का जिक्र है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एस्टीन से उनकी मुलाकात केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के तहत हुई थी।

बांग्लादेश में जमात ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उन्होंने कहा, “भारत और बांग्लादेश एक-दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं और हमें साथ मिलकर काम करना होगा।”
इस बयान को इस रूप में देखा जा रहा है कि जमात, अपने पुराने इतिहास और पहले पाकिस्तान समर्थक रुख के बावजूद, भारत के साथ काम करने की संभावना तलाशने के लिए तैयार है। हाल के महीनों में भारत से दूरी बनाकर रखना बांग्लादेश के लिए फायदेमंद नहीं रहा है और यह सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश की ज्यादातर जमीनी सीमा भारत से लगती है। हालांकि बांग्लादेश के जानकारों के अनुसार, बीएनपी अभी आगे मानी जा रही है, लेकिन जमात ने उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की है, जहाँ पहले वह कमजोर थी। पार्टी पर लगा प्रतिबंध

हटने के बाद उसने यह बढ़त हासिल की है और अब वह बहुमत हासिल करने का लक्ष्य रख रही है। जमात के अमीर डॉ. शफीकुर रहमान ने कहा, सिर्फ एक साल पहले मेरी पार्टी को कमजोर माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि हमें बहुत कम सीटें मिलेंगी। आज जमात बहुमत के करीब खड़ी है। यह जनता की इच्छा है। जब जनता एकजुट होती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता।”

रितु तावड़े ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
महापौर तावड़े और उपमहापौर घाड़ी शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करेंगे और राज्य सरकार इस कार्य में उनका पूरा सहयोग करेगी।

TRUE VALUE

खरीदे प्री-ओनर्ड गाड़ी 1 साल तक की वारंटी के साथ, सिर्फ TRUE VALUE पर

CELEBRATING 60Lakh

STORIES OF TRUST

TRUE VALUE

CERTIFIED

376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स

वेरिफाइड कार हिस्ट्री*

1 साल तक की वारंटी और 3 फ्री सर्विस*

यहाँ ऐप डाउनलोड करें

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruevalue.com

SIKAR- NEAR D.T.O OFFICE, JAIPUR ROAD, JHUNJHUNU, AURIC MOTORS PVT. LTD.: 7230003521, 7412059847, 7412087309 | JAIPUR – JHUNJHUNU BYPASS, NEAR PIPRALI CHORAHA, SIKAR, JAMU AUTOMOBILES: 9694097851, 9694095757, 9887048515 | CHURU: T.R SAWHNEY MOTORS PVT. LTD. OPP. HOTEL GRAND SHEKHAWATI, JAIPUR ROAD: 8882898919.

राष्ट्रदूत (एचयूपएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वलन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, एन.एन.आई. नं. **RAJHIN/2009/28296** जयपुर कार्यालय: सुघर्म एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●